शहरः सूरत
राज्यः गुजरात

श्रेणीः व्यापार और औद्योगिक केंद्र, टायर 2

सूरत, गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और सूरत जिले की प्रशासनिक राजधानी भी है। भारत देश में नौंवा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है, और इसने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है जैसे कि विश्व का चौथा सबसे तेज विकासशील वाला शहर (सिटी मेयर्स फाउंडेशन 2011), और भारत में प्रथम 'स्मार्ट आईटी' शहर (माइक्रोसॉफ्ट 2014)। वर्ष 1994 में सूरत एक भयंकर महामारी का शिकार हुआ था, जिसने इस शहर को पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर कर दिया, इसके परिणामस्वरूप, सूरत आज भारत के तीसरे सबसे साफ-सुथरे शहरों की श्रेणी में आता है। अपने हीरे तथा वस्त्र उद्योग की मजबूती के कारण, सूरत देश के उन दस शीर्ष शहरों की गिनती में भी आता है जो सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाल के वर्षों में, कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय स्थापित करने के साथ ही सूरत ने एक लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है।

1. जनसांख्यिकी प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
कुल जनसंख्या	4467797	25745083	377,106,125
यूए की कुल जनसंख्या (यदि)	4591246		
जिला शहरी आबादी में यूएलबी आबादी की हिस्सेदारी (%)	92.13		
जनसंख्या वृद्धि दर (एईजीआर) 2001-11	6.07	3.07	2.76
क्षेत्र (वर्ग मीटर)*	335.82		
जिले में यूएलबी क्षेत्र का हिस्सा (%)*	7.38		
जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति वर्ग प्रति किमी)*	13304		
साक्षरता दर (%)	87.89	86.31	84.11
अनुसूचित जाति (%)	2.36	6.96	12.60

अनुसूचित जनजाति (%)	2.95	3.48	2.77
युवा, 15-24 वर्ष (%)	22.02	19.85	19.68
स्लम जनसंख्या (%)	10.46	14.92	17.36
कार्य आयु समूह, 15-59 वर्ष (%)	68.32	66.31	65.27

स्रोतः भारत की जनगणना, 2011

*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

#एक से अधिक जिले में फैले हुए शहरी स्थानीय निकाय

2. आर्थिक प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
2004-05 के स्थायी कीमत पर प्रति व्यक्ति आय (रु.)*	लागू नहीं	48301	रु. 35,947[a]
शहरी गरीबी का अनुपात (शहरी आबादी का %)**	5.61	10.2	13.7
बेरोजगारी दर, 2011-12***	0.29	0.8	3.4
कार्य करने वालों की दर, 2011-12***	42.20	38.4	35.5
कार्य की स्थिति, 2011-12 (प्रतिशत)*** स्व नियोजितः नियमित/मजदूरी वेतनभोगी कर्मचारीः अनौपचारिक श्रम।	 37.10 57.05 5.85	 41.6 49.6 8.9	 42.0 43.4 14.6
मजदूरों का क्षेत्रवार वितरण, 2011-12 (प्रतिशत)*** प्राथमिक द्वितीय तृतीयक	 0.28 66.10 33.63	 4.8 48.7 46.4	 7.5 34.2 58.3
प्रमुख व्यवसायों द्वारा मजदूरों का वर्गीकरण, 2011-12 (प्रतिशत)*** व्यवस्थापक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक	27.93	15.7	15.8

व्यवसाय तकनीशियनों और एसोसिएट पेशेवर क्लर्क सेवा श्रमिक और दुकान एवं मार्केट सेल्स श्रमिक कुशल कृषि एवं मत्स्य श्रमिक शिल्प और संबंधित ट्रेडों के श्रमिक प्लांट और मशीन ऑपरेटरों और संयोजनकर्ता (अस्सेम्ब्लेर्स) एलिमेंटरी व्यवसाय श्रमिक कब्जे से वर्गीकृत नहीं	1.79 6.05 1.29 6.49 0.00 13.54 34.46 8.44 0.00	4.0 6.0 4.2 15.0 2.5 19.0 19.6 14.0 0.0	8.8 6.7 5.0 14.7 4.6 19.2 9.2 16.1 0.1
प्राथमिक वस्तु निर्माता#	कला रेशमी कपड़े जरी का सामान हीरे (डायमंड्स)		
प्रमुख उद्योग##	मशीनरी, मशीन टूल्स तथा इसके पार्ट्स टेक्सटाइल रसायन एवं पैट्रोरसायन उत्पादन		
अनुमोदित एसईजेड की संख्या	1	38	413

नोटः 2009-10, 2010-11, 2011-12 का 3 वर्ष औसत

स्रोतः *सभी भारत- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय

**राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की यूनिट लेबल डाटा, भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय, 68वां राउंड, 2011-12

***राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की इकाई स्तर डेटा, भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, 68वां राउंड, 2011-12

#जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

##जिला औद्योगिक प्रोफाइल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार

∞ वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

3. अवसंरचना स्थिति

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
घर के अंदर नल के पानी का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत (बनाये गए स्रोतों से)	80.50	68.78	84.14
बिजली के उपयोग के साथ घरों का %	98.88	97.19	92.68
घर के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का %	93.55	85.17	72.57
गंदे पानी के माध्यमों का ड्रेनेज से जुड़े परिवारों का प्रतिशत	96.26	82.64	81.77
सीवरेज प्रणाली का प्रकार*	भूमिगत सीवरेज प्रणाली		
ठोस अपशिष्ट प्रणाली का प्रकार*	द्वार से द्वार		
कम्प्यूटर/लैपटॉप का इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत कम्प्यूटर/लैपटॉप का बिना इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	5.07 8.12	6.38 9.25	8.27 10.40
मोबाइल फोन के उपयोग के साथ घरों का %	71.42	65.92	64.33
आवास का स्वामित्व पैटर्न (%) स्वामित्व किराए पर	 54.60 42.98	 72.52 24.28	 69.16 27.55
भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वाले परिवारों का %	49.06	35.79	32.94
संकेतक	**शहर (नगर निगम)**		
प्रति 1,00,000 लोगों पर अस्पतालों की संख्या*	0.02		
प्रति 1,00,000 लोगों पर स्कूलों की संख्या*			
प्राथमिक	19		
माध्यमिक	लागू नहीं		

द्वितीयक	10
महाविद्यालय	2

स्रोतः मकान, घरेलू सुविधाओं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

4. राजनीतिक प्रोफाइलः नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचा

शासन की वास्तुकला *चुने गए एवं कार्यकारी निकायों की संरचना। पदानुक्रम के संकेत दें।*	सूरत नगर निगम (एसएमसी) की अभिशासी संरचना में दोनों अर्थात् राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्कंध शामिल हैं। राजनीतिक स्कंध एक निर्वाचित निकाय है जिसमें चुने गए पार्षदों के मुखिया महापौर होते हैं। एक उप महापौर, महापौर की सहायता करते हैं और ये दोनों ही निर्वाचित पार्षदों में से चुने जाते हैं। महापौर एवं उप महापौर का सेवाकाल पांच वर्षों का होता है। प्रशासनिक स्कंध का नेतृत्व नगर निगम आयुक्त द्वारा किया जाता है जो कि निगम के रणनीतिक तथा परिचालनगत नियोजन तथा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। आयुक्त, निगम में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, पार्षदों को शामिल करते हुए गठित किए गए बोर्ड अथवा स्थायी समिति की ओर से निर्णय लेता है। गुजरात में नगरीय प्रशासन, शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग की परिधि के अंतर्गत आता है। राज्रू में शहरी क्षेत्र के लिए यह एक नीति निर्माता निकाय है और स्थानीय अधिनियमों में निर्दिष्ट अनुसार कार्यों को हाथ में लेता है। वर्ष 1994 के पश्चात, एसएमसी की प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें एक उर्ध्वाधर कठोर-श्रेणीबद्ध प्रणाली से एक क्षैतिज ओर अधिक परस्पर क्रियाशील प्रणाली में बदलाव शामिल है। 'स्थल स्तरीय परिचालनों' में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। प्रशासन का विकेन्द्रीकरण इस बदलाव में एक अहम पहलू रहा है। शहर को सात जोनों में बांटा गया है, नामतः वरछा (पूर्व), रान्देर (पश्चिम), कटरगाम (उत्तर), उढना (दक्षिण), लिंबायत (दक्षिण-पूर्व), अथवा लाइन्स (दक्षिण-पश्चिम) और मुगलीसारा (मध्य)। प्रत्येक जोन को स्थानीय समस्याओं के समाधान और स्रोत पर उनके निबटान हेतु पूर्ण प्राधिकार प्रदान किया गया है। आगे, पारदर्शिता एवं समग्र निर्णय इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया के प्रमुख तत्व बन चुके हैं।

	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए) व्यवस्थित तौर पर विकास करने एवं अनियोजित तथा अनधिकृत विकास को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए, एसयूडीए विकास योजनाओं तथा नगर निवेश योजनाओं को तैयार करता है।
निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.	116
निर्वाचन विवरण* *चुनाव चक्र, पिछला चुनाव, नाम, जहां प्रासंगिक हो पार्टी की संबंद्धता, मुख्यमंत्री, आयुक्त एवं महापौर के लिए कार्यालय ग्रहण करने की तारीख।*	भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री हैं। उन्हें 22 मई 2014 को निर्वाचित किया गया था। जुलाई 2014 से श्री मिलिंद टोरवाडा आयुक्त हैं। परिषद का नेतृत्व बीजेपी की महापौर श्री निरंजन जांजमेरा द्वारा किया जाता है, जो जून 2013 में निर्वाचित हुई। नगर निगम के चुनाव वर्ष 2015 में आयोजित किए गए थे।

स्रोतः *संबंधित यूएलबी वेबसाइट और मीडिया सर्च

5. शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का कार्यनिष्पादन

क्रेडिट और कर

शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग (नवम्बर 2012 तक)*	एए
संपत्ति कर#	कवरेज (%): 100% संग्रह क्षमता (%): 92% राशि (रु.): 355.88 करोड़ (2012-13)

स्रोतः *www.jnnurm.nic.in

#रिफॉर्म मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

शहरी स्थानीय निकायों में ई-शासन एवं कम्प्यूटरीकरण

सुधार	स्थिति (कार्यान्वित, प्रगति में और किसी भी टिप्पणी में)
संपत्ति कर*	कार्यान्वित

लेखांकन*	कार्यान्वित
जल आपूर्ति और अन्य सुविधाएं*	कार्यान्वित
जन्म और मृत्यु पंजीकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम*	कार्यान्वित
नागरिक शिकायत निगरानी*	कार्यान्वित
कार्मिक प्रबंधन प्रणाली*	कार्यान्वित
निर्माण योजना अनुमोदन*	कार्यान्वित
ई-प्रापण	कार्यान्वित
क्या नागरिक अपने बिल एवं करों का भुगतान सिटिजन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) पर कर सकते हैं?#	केवल सीएफसी पर
क्या शहरी स्थानीय निकायों पर भुगतान करने की ऑनलाइन सुविधा है#	हाँ
शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किया जाने वाला ई-मेल सॉफ्टवेयर क्या है#	एनआईसी
क्या शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)/वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं#	हाँ
क्या आप स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी) का उपयोग करते है?#	नहीं
क्या शहरी स्थानीय निकाय की स्वयं की वेबसाइट है#	हाँ https://www.suratmunicipal.gov.in
74वें सीएए का कार्यान्वयन#	शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित सभी कार्य

नोटः *शहरी स्थानीय निकाय में ई-गवर्नेंस के मॉड्यूल कार्यान्वित

स्रोतः *सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

मान्यता

राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सम्मानों, पुरस्कारों, पायलटों, क्षैतिज नेटवर्कों की सूची।	• आईसीएलईआई के सदस्य • एसीसीसीआरएन परियोजनाएं • रॉकफेलर 100 लचीले शहर • इंडिया टुडे बेस्ट सिटी अवार्ड्सः बेस्ट इमर्जिंग इन इकोनोमी केटेगरी; बेस्ट इमर्जिंग सिटी इन क्राइम एंड सेफ्टी • स्कॉच अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस - गोल्ड 2014 • नागर रत्ना 2011 (इनोवेशन) • अन-हैबिटेट दुबई बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड 1998 • उत्कृष्टता के जेएनएनयूआरएम पुरस्कारः बेस्ट पीपीपी अवधारणा (2008); बेस्ट एनवायर्नमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट (2008); बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ रिफार्म (2007)

6. वित्तीय एवं स्वास्थ्य

वित्तीय

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग के साथ घरों का %*	53.51	66.09	67.77

वित्तीय स्थिति#		
नगर निगम के आय और व्यय का विवरण (लाख रु. में)	आय	व्यय
2009-10	147951.00	173618.00
2010-11	159532.00	172113.00

2011-12	187027.00	163676.00
नगरीय गरीबों के लिए आरक्षित बजट का प्रतिशत@	लागू नहीं	

स्रोतः मकान, घरेलू सुविधाएं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

@ जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट

पर्यावरण

स्वच्छ भारत रैंकिंग*	63
उपलब्ध शहरों के लिए व्यापक पर्यावरण आकलन#	57.9

स्रोतः *प्रेस सूचना ब्यूरो, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2015

#केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, 2009

7. क्षमताः ट्रैक रिकार्ड और पहल

जेएनएनयूआरएम परियोजनाएं	स्थिति या टिप्पणी			
बीएसयूपी/आईएचएसडीपी	बीएसयूपी योजना के तहत कुल 12 परियोजनाएं (अधोसंरचना के लिए 1 एवं आवास के लिए 11) स्वीकृत हुए जिसमें से 8 परियोजना पूरी हो चुकी है। परियोजना की कुल लागत रु 696.73 करोड़ थी। आवास परियोजना का हिस्सा 98 प्रतिशत (रु. 686.15 करोड़) एवं अधोसंरचना परियोजना का हिस्सा 2 प्रतिशत (रु. 10.58 करोड़) है। 11 आवासीय परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जबकि आवास पर 3 परियोजनाएं और 1 बुनियादी ढांचे पर कार्य प्रगति पर हैं। 97 प्रतिशत घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।			
यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी	यूआईजीः कुल 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी जिसमें से 19 परियोजनाओं को पूरा कर दिया गया है। कुल 8 परियोजनाएं प्रगति में है।			
परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	200533.07			
परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा	क्षेत्र	परियोजनाओं	कुल लागत (लाख रु.	कुल स्वीकृत

		की सं.	में)	परियोजनाओं में क्षेत्र की हिस्सेदारी
	जल	8	79907.04	39.8
	जल निकासी/ एसडब्ल्यूडी	2	8421.82	4.2
	सीवरेज	10	48943.98	24.4
	एसडब्ल्यूएम	1	5249.72	2.6
	परिवहन	6	58010.51	28.9
केन्द्र द्वारा जारी सहायता का हिस्सा (प्रतिशत)	86.30			
पूरा किए हुए कार्य का प्रतिशत (वास्तविक प्रगति)	55			
उपयोग किया गया वित्त (प्रतिशत)	90.08			

स्रोतः www.jnnurm.nic.in (नवम्बर, 2015 तक पहुंच)

शहरी विकास मंत्रालय की योजनाओं के साथ एकत्रीकरण	स्थिति, टिप्पणी
विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)	लागू नहीं
अमृत	शहर अमृत मिशन के तहत शामिल है। राज्य वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की जा चुकी है।
जेएनएनयूआरएम	शहर जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक तहत कवर था।
एनयूआईएस	शहर एनयूआईएस के तहत कवर है
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)	लागू नहीं

स्रोतः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार